

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2105/2022

उपेन्द्र जागा

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख राजस्थान, जयपुर।
3. श्री लखन सिंह, सर्वेयर, भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.06.2022

आदेश की दिनांक : 10.08.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य

एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सर्वेयर के पद पर भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.06.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय उप वन संरक्षक, बाड़मेर 650 कि.मी. दूर निजी प्रत्यर्थी संख्या-3 को समंजित करने के किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्वयं के स्थानान्तरण हेतु कोई आवेदन नहीं करने के बावजूद अपीलार्थी का स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण मानते हुए स्थानान्तरण किया गया है तथा कोई यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं किया गया, जो राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 17(1)(4) का उल्लंघन है। अपीलार्थी के बुजुर्ग पिता गंभीर लीवर की बीमारी से पीड़ित है। (अनुलग्नक-4) उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी एक मात्र व्यक्ति है। अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सर्वेयर के चार पद सजित है, जिनमें से दो पद भरे हुए हैं तथा दो पद रिक्त हैं। अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। अतः उपरोक्त स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण निरस्त किया जाकर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रखा जावे।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.06.2022 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को सर्वेयर के पद पर भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि), बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त लाभ प्रदान किए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 25.06.2022 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर से कार्यालय उप वन संरक्षक, बाड़मेर किया गया तथा अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है। इस संबंध में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12998/2021 मनीष खींची बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 में वर्णित है कि:-

"Heard learned counsel for the petitioner and perused the record.

A perusal of the order dated 14.08.2021 assailed in the appeal reveals that as many as 372 employees were transferred thereunder. Clause 7 at the bottom of the transfer order reads as under:-

"7.1" (3 of 3) [CW-12998/2021] By Clause 7, it was meant that whosesoever is transferred on his request, is disentitled for TA/DA and by no stretch of imagination it can be held that all the employees under transfer vide order dated 14.8.2021, were disentitled for payment of TA/DA. This aspect has been appreciated by the learned Tribunal while passing the order dated 22.10.2021. Even otherwise also, judgment of Coordinate Bench of this Court in case of Sharwan Kumar Prajapat versus State of Rajasthan, SB Civil Writ Peition No. 7341/2020, says that an order of transfer cannot be set aside merely because no TA/DA has been made payable even if the transfer was not on his request, which can always be directed to be paid.

In view thereof, this Court does not find any perversity or illegality in the order impugned dated 22.10.2021 warranting interference of this Court.

The writ petition is dismissed accordingly."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में भी यह विनिश्चय किया गया है कि स्थानान्तरण आदेश में यात्रा भत्ता आदि दिए जाने के उल्लेख नहीं किए जाने मात्र से स्थानान्तरण आदेश दोषयुक्त नहीं माना जा सकता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों की रोशनी में आलोच्य आदेश में यात्रा भत्ता देय होने के बारे में अंकन नहीं होने के कारण दोषयुक्त नहीं माना जा सकता है। अतः अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 25.06.2022 (अनुलग्नक-1) के संबंध में स्थगन

का आधार नहीं है। अतः अपोल सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग विभाग को आदेश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल संबंधित नियमों के अनुसार देय होगा। अतः नियमानुसार दिए जाने की कार्यवाही की जावे।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांकको हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य